आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)

सोमवार 24.03.2026 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। कहा– उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में बनाई नई पहचान।
- प्रदेश की सड़कों की मरम्मत, बाढ़ सुरक्षा, स्कूलों के सुधार और अन्य विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 54 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने प्रदेश में एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा की। घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों की मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 25 करोड़ की धनराशि मंजूर की।

प्रधानमंत्री बधाई संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना जैसे प्रयासों से प्रदेश में विकास को गति मिली है।

उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। साथ ही महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए कार्यों को भी महत्वपूर्ण बताया।
प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और 'विकसित भारत' के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सरकार के चार साल

प्रदेश में सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर "जन–जन की सरकार, चार साल बेमिसाल" कार्यक्रम राज्यभर में धूमधाम से आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया और सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

राज्यभर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही और सरकार के कार्यों को सराहा गया।

हरिद्वार, चम्पावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी सहित विभिन्न ज़िलो में आयोजित कार्यक्रमों में शिविर, प्रदर्शनी और स्वास्थ्य जांच जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों, किसानों और अन्य लाभार्थियों को चेक, उपकरण, किट और अन्य सहायता सामग्री वितरित की गई।

कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इन प्रयासों के माध्यम से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।

शिक्षा व्यवस्था मजबूती

उत्तराखंड में पिछले चार वर्षों में विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को विकसित करते हुए

छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। इस दौरान राजकीय विद्यालयों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया गया और नवाचारों को बढ़ावा दिया गया। एक रिपोर्ट–
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अलग–अलग वर्षों में लाखों छात्र–छात्राओं को करोड़ों किताबें वितरित की गई हैं। इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में कक्षा 1 से 12 तक के लगभग नौ लाख छात्रों को निःशुल्क नोटबुक भी दी जा रही हैं।

बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी सुधार देखा गया है। हाईस्कूल का परीक्षाफल प्रतिशत वर्ष 2022 के 77 दशमलव 4–7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 90 दशमलव 7–7 प्रतिशत हो गया है। वहीं इंटरमीडिएट का परीक्षाफल भी बेहतर हुआ है।

मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत हजारों छात्र–छात्राओं को लाभ दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में 559 क्लस्टर विद्यालयों का चयन किया गया है, जहां स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास और आधुनिक प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले चार वर्षों में छात्रों ने विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक हासिल किए हैं। वहीं भारत–दर्शन शैक्षिक भ्रमण योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। पिछले चार वर्षों में विभिन्न पदों पर चार हजार से अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है, जिससे विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को और मजबूती मिली है।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है और हर छात्र को गुणवत्तापरक तथा व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुन्द्रियाल

शुरुआत
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज सौ दिन – टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में श्री नड्डा टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का भी शुभारंभ करेंगे।
विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि क्षय रोग आज भी एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है और विश्व में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान ने शीघ्र निदान का विस्तार करने, निशुल्क उपचार सुनिश्चित करने, पोषण संबंधी सहायता को मजबूत करने और रोगी की देखभाल में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मोचन निधि के तहत प्रदेश की सड़कों की मरम्मत, बाढ़ सुरक्षा, स्कूलों के सुधार और अन्य विकास कार्यों के लिए कुल 54 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

इसके तहत चम्पावत क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न गांवों में सुरक्षा दीवार निर्माण, प्रवेश द्वार और सड़क निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।
आपदा से प्रभावित देहरादून, बागेश्वर और उत्तरकाशी जिलों में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई है। इसके अलावा खटीमा क्षेत्र में ग्राम्य विकास से जुड़े कार्य, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण तथा अल्मोड़ा के सोमेश्वर क्षेत्र में सिंचाई गूल निर्माण के कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।

गैस उपलब्धता समीक्षा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने प्रदेश में एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों की मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संस्थानों को भी निर्बाध गैस आपूर्ति मिलनी चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारियों को एलपीजी राज्य समन्वयकों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी श्रेणी में अपडेट करने और पीएनजी गैस कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दिया। साथ ही व्यावसायिक संस्थानों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने गैस के विकल्प के रूप में पिरुल ब्रिकेट को बढ़ावा देने की भी बात कही, जिससे एलपीजी की खपत कम होने के साथ चीड़ के जंगलों में पिरुल के निस्तारण में भी मदद मिल सकेगी।

मंजूरी

प्रदेश में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों की घेरबाड़ के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सहायता किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज देश अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में धार्मिक औरं सांस्कृतिक स्थलों के पुनरोद्धार और विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं।

चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित माँ कालिका मंदिर, पलटन बाजार में पहुंचकर विधि–विधान से पूजा–अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की।

श्री धामी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के लिए बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत व्यापक कार्य किए जा रहे हैं, जबकि केदारनाथ धाम में आपदा के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्यों ने पूरे विश्व में एक मिसाल प्रस्तुत की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा।